

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2016 निगरानी

1. नाथू } पि0 स्व0 गोपाल जाति धोबी निवासी ग्राम सलेमपुरा
2. रामजीलाल } तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजू पुत्र छोटया जाति धोबी निवासी सलेमपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत सलेमपुरा जरिये सरपंच

गैरनिगरानीकार

निगरानी अ.धा. 97 राज. पंचायत राज अधि0 विरुद्ध पट्टा आदेश
दिनांक 07.05.1993 जो अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा
गैर निगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया है।

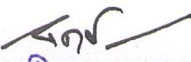


उपस्थिति : पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
: श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

—:निर्णय:—

दिनांक: 20.02.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पट्टा एकदम खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा जो राजू पुत्र छोटया जाति धोबी के नाम जारी किया गया है इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सलेमपुरा में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा जारी करते समय राज. पंचायत राज अधि. 1994 की धारा 140 से लेकर 162 तक जो कायदे कानून बने हुए हैं उनकी पालना नहीं की है तथा पट्टा फार्म भरकर अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी कर दिया। आबादी भूमि का पट्टा जारी करने से पहले पट्टा चाहने वाले व्यक्ति के आवेदन को दर्ज किया जाता है। वार्ड पंचो द्वारा मौका देखने के पश्चात सारी कानूनी कार्यवाहियों को पूरी करते हुए पट्टा जारी किया जाता है। परन्तु जिस व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किया गया है वह व्यक्ति ग्राम पंचायत सलेमपुरा में नहीं है। प्रार्थी सं. 01 के प्रश्नगत पट्टे की आड में प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर जबरन कब्जा कर


अति० जिला कलक्टर
दौसा

निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहा है। जिसका उसे कोई अधिकारी हासिल नहीं है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.07.2016 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष जैरकार प्रकरण नाथू बनाम कजोड में प्रार्थना पत्र टी.आई के जवाब के साथ प्रश्नगत पट्टे की प्रति पेश करने पर हुई। अतः ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 को निरस्त करवाने हेतु निगरानी पेश की है।



निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टा पत्रावली खाली है, प्रार्थना पत्र लगा हुआ है, प्रार्थना पत्र के आधार पर ही पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा सरपंच, सचिव, पक्षकार आदि किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आदेशिका फार्म खाली लगे हैं। राजू पुत्र छोट्या नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। राजू पुत्र कजोड अवश्य है। गैर निगरानीकार का कोई कब्जा नहीं है। मेरी कब्जे की भूमि पर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया है। पंचो द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया। पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तथा पट्टा अवैध रूप से जारी किया गया है। अतः अप्रार्थी सं. 01 को जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि निगरानीकार पट्टा जारी होना स्वीकार करते हैं। रामजीलाल के द्वारा दिनांक 26.09.1991 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो पत्रावली में लगा हुआ है। निगरानीकार को निर्माण की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि इनका उस भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। इस पत्रावली में कोई भी पट्टा जारी होना या इनका कब्जा होना साबित नहीं होता है। रामजीलाल, गोपाल, कजोड, छोट्या(फौत होने पर राजू के नाम पगडी) कब्जे की भूमि थी। गोद जाने का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है, किन्तु सामाजिक क्रियाकर्म के अनुसार वह गोद पुत्र हो गया। अतः राजू पुत्र छोट्या है। 1993 में राजू ने आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर दिया। हमें राजस्थान पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत नियम 1958 के तहत पट्टा जारी किया गया है। जो की निःशुल्क है इसमें कोई शुल्क या नजराना जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है और न ही आवेदन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सू-मोटो पट्टा जारी कर सकती है। सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अस्थायी निषेधाज्ञा से निर्माण रूकवाना चाहते थे किन्तु उसमें टी.आई. नहीं मिली। कब्जे का बिन्दु सिविल कोर्ट तय करेगा। पट्टा गलत जारी होने का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 15/2016 निगरानी

कोई प्रमाण नहीं है। 15 वर्ष पूर्व आग लगने से पट्टा जल गया था। न्यायालय में फोटो प्रति पेश की गई है। सिविल न्यायालय में दावा चल रहा होने से पट्टे के संबंध में निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

पुनः बहस में अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि पट्टे की सत्यता की जाँच करने का अधिकार इस न्यायालय को है। आवेदन बाकायदा सयुक्त रूप से कजोड, नाथू, राजू, रामजीलाल द्वारा किया गया है। अतः तीनों भाईयों की सयुक्त कब्जा की आबादी भूमि है। पट्टे की कार्यवाही तीनों भाईयों की चली एवं बाद में गैर निगरानीकार सं. 01 ने स्वयं के अकेले के नाम पट्टा जारी करवा लिया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर में यद्यपि राजू पुत्र छोटू धोबी को आवंटन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लिया हुआ है। किन्तु पट्टा पत्रावली में प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 01 के हस्ताक्षर नहीं है। नजरी नकशा संलग्न है किन्तु उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली की आदेशिकाओं पर कोई अंकन नहीं है। प्रश्नगत पट्टे की प्रति भी ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख के साथ उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत सलेमपुरा प. स. लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा गैरनिगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.05.1993 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत सलेमपुरा प. स. लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर,
दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर,
दौसा